भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2516

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

हरियाणा के लिए एक अलग उच्च न्यायालय

+2516. श्री वरुण चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार के पास हरियाणा राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हाँ, तो इसकी स्थापना के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

हरियाणा सरकार ने, हरियाणा राज्य के लिए चंडीगढ़ में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए अनुरोध किया है । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा पंजाब राज्य सरकार से इस विषय में उनके विचार मांगे गए थे । पंजाब सरकार प्रस्ताव के साथ सहमत नहीं हुई थी । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने पूर्ण न्यायालय की बैठक में किसी भी प्रकार का विचार न देने का संकल्प किया था । वर्तमान में, सरकार के पास हरियाणा राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****